भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1153
उत्तर देने की तारीख- 23 मार्च, 2012

बीएसएनएल संघ की मांगें

1153. श्री श्यामल चक्रवर्ती :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीएसएनएल संघ/कार्यपालकों एवं गैर-कार्यपालकों के संघों की संयुक्त कार्यवाही समिति (जेएसी) ने इस कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता को बेहतर बनाने हेतु चर्चा करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबंधन के समक्ष कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो जेएसी द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में जेएसी की मांगों को समायोजित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के संघों/यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने अपने मांग-पत्र (चार्टर) में निहित अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल का एक नोटिस दिया था। इस मांग-पत्र में शामिल मांगें मुख्यत: बीएसएनएल के स्टाफ संबंधी मुद्दों से संबंधित थीं। तथापि, बीएसएनएल/सरकार द्वारा उन मांगों, जो कंपनी की वित्तीय व्यवहार्यता और जो ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी हुई हैं, पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है :-

क्रम संख्या	मांग	बीएसएनएल/दूरसंचार विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
1.	उपकरण की तत्काल प्राप्ति एवं आपूर्ति तथा महत्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन।	बीएसएनएल ने उपकरण की प्राप्ति एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक परियोजनाओं के पूरा किए जाने के लिए पहले ही समुचित कदम उठाए हैं।
2.	समुचित क्रियाविधि की मार्फत अभिगम घाटा प्रभारों (एडीसी) का परिमाणन एवं हानि वहन करने वाली ग्रामीण सेवाओं की हानि की क्षतिपूर्ति करना।	बीएसएनएल ने अभिगम घाटा प्रभार (एडीसी) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने पर ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों के बारे में मदद जारी रखने की मांग की है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मदद के रूप में 600 करोड़ रूपए की अंतरिम अनुशंसा की है।